

## **To Construct the Road**

**646. Shri Chiranjeev Rao, M.L.A.:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from villages Khyaliawas to Khatawali by the Haryana State Agriculture Marketing Board ?

**JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE & FARMERS WELFARE MINISTER**

No, Sir.

### **Detailed Information pertaining to the Assembly Q. No. 646**

## **To Construct the Road**

**Shri Chiranjeev Rao, M.L.A.**

### **Villages Khyaliawas to Khatawali:-**

The length of the proposed road is 2.10 km. The width of available consolidation path is 4 karam in the entire length. As per approved policy, the HSAM Board constructs roads on Kutchha paths having width of consolidation path as 5 karam and further which shortens distance to reach the nearby Market Yards. This proposal is not covered under the road construction policy of the Board due to less width of consolidation path and not shortening of distance to reach nearby Market Yard. There is no proposal under consideration of the Government to construct this road.

## सड़क का निर्माण करना

646. श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गांव खयालियावास से खातावाली तक सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा  
जी नहीं, श्रीमान् ।

अतांराकित प्रश्न संख्या 646 से सम्बंधित विस्तृत जानकारी

## सड़क का निर्माण करना

श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.

गाँव खयालियावास से खातावाली :- प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 2.10 किलोमीटर है। सम्पूर्ण लम्बाई में राजस्व रास्ते की चौड़ाई 4 करम है। स्वीकृत नीति के अनुसार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड उन कच्चे रास्तों को पक्का करता है जिनमें राजस्व रास्ते की चौड़ाई 5 करम हो तथा इसके बनने से नजदीकी मंडी में जाने के लिए दूरी कम होती हो। यह प्रस्तावित सड़क राजस्व रास्तों की चौड़ाई कम होने व नजदीकी मंडी से दूरी कम न होने के कारण बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अंतर्गत नहीं आती। इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।